International Conference – 2025: Developed India @ 2047
Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025
Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

लोकतंत्र एवं जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका

डॉ बिन्दु सोरेंग

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, गोस्सनर कॉलेज, रॉची

शोध सारांष

मीडिया की भूमिका जनमत निर्माण और लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है और ही भी क्यों न, इसे लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में जो जाना जाता है, अर्थात मीडिया ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी सूचना, संदेष अथवा अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुचाया जाता है । मीडिया ही जनता को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की जानकारी देता, सरकार एवं प्रषासनिक नीतियों की समीक्षा करता एवं गलतियों को उजागर करता है । अतः मीडिया को पक्षपातपूर्ण एवं व्यवसायिक हितों से प्रभावित होने से कैसे रोका जाए, निष्पक्ष, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि जनमत सही दिषा में निर्मित हो सके और लोकतंत्र सषक्त बनें । प्रस्तुत आलेख में इस बात को विष्लेषित करने का प्रयास किया जाएगा कि मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाने में कितना हद तक सफल रही है, साथ ही मीडिया के खतरे जैसे गलत सूचना एवं प्रचार, पक्षपात, पत्रकारों पर हमले, ध्रुवीकरण इत्यादि समस्याओ के समाधान को खोजने का प्रयास किया जाएगा ।

Keyboard - चौथा स्तंभ, प्रषासनिक नीति, लोकतांत्रिक मूल्य, निष्पक्ष, ध्रुवीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) नागरिकों को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है । इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिक इस स्वतंत्रता का प्रयोग सिर्फ मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप में चाहे वह मीडिया, चित्र, बैनर अथवा भाषण के रूप में भी कर सकते हैं ।

मीडिया की भूमिका जनमत निर्माण और लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

International Conference – 2025: Developed India @ 2047
Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025
Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली अपनायी गई है, भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है,

मीडिया का प्रमुख कार्य निष्पक्ष, सत्य और स्वतंत्र रूप से सूचनाओं को प्रसारित करना, सत्ता तंत्र की जवाबदेही तय करना और जनमत तैयार करना होता है । आज जीवंत लोकतंत्र की असली परीक्षा मीडिया की स्वतंत्रता है, अतः वर्तमान में इस स्वतंत्रता का प्रयोग मीडिया द्वारा ईमानदारीपूर्वक किया जा रहा है या फिर आज मीडिया अलग-अलग राजनीतिक दलों की वकील या बड़े-बडे उद्योगपतियों की आवाज बन गई है ।

वर्तमान परिदृष्य में मीडिया की भूमिका को लेकर कई चुनौतियॉ सामने आयी है, जो निम्नलिखित है -

1. पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग –

वर्तमान में यह देखा गया है कि कई मीडिया संस्थान राजनीतिक दलों या अन्य प्रभावषाली समूहों के प्रति झुकाव रखते हैं, कुछ अखबार एवं न्यूज चैनल्स किसी विषेष राजनीतिक पार्टी के सर्मथन में खबरें दिखाते हैं और विपक्षी दलों की आलोचना को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, कुछ चैनल सरकार की नीतियों की केवल प्रषंसा करते हैं, और उनकी विफलताओं पर चर्चा करने से बचते हैं, जबकि कुछ चैनल विपक्ष की नीतियों को जरूरत से ज्यादा नकारात्मक रूप में दिखाते हैं,

चुनावों के दौरान देखा जाता है कि कुछ मीडिया संस्थान एक दल की रैलियों को ज्यादा कवरेज देते हैं जबकि दूसरे दलों की रैलियों को कम महत्व देते हैं । यदि कोई सरकार विरोधी प्रदर्षन होता है तो कुछ मीडिया वाले इसे श्अराजकता या देषद्रोहश् का नाम देते हैं जबकि कुछ इसे श्जनता की आवाजश् के रूप मे पेंष करते हैं, जब कोई बड़ा घोटाला सामने आता है तो कुछ मीडिया चैनल इस प्रमुखता से दिखाते हैं जबकि कुछ इसे नजर अंदाज कर देते हैं क्योंकि इससे उनक समर्थित राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता है ।

मीडिया का पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग वर्तमान लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह जनता की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है ।

2. फेक न्यूज (झूठी खबरें) एवं भ्रामक जानकारी -

झूठी खबरें (फेक न्यूज) आज के डिजिटल युग में एक गंभीर चुनौती बन गई है जो समाज में भ्रम और गलतफहमी फैलाती है । फेक न्यूज का अभिप्राय ऐसी खबरों से है जिनका उपयोग जानबूझकर पाठकों को गलत सूचना देने अथवा धोखा देने के लिए किया जाता है, भारत जैसे देष में यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है तथा इसके कारण अकसर सड़क पर दंगे और मॉब लिंचिंग की घटनाए देखने को मिलती है । फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोषल मीडिया प्लेटफार्म श्फेक न्यूजश् प्रसारण के प्रमुख स्रोत बन गए हैं ।

भारत में व्हाट्सएप को श्फेक न्यूजश् के लिए सबसे अधिक असुरक्षित माध्यम माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग करने वाले लोग अकसर खबर की सत्यता जाने बिना इसे कई लोगों को फारवर्ड कर देते हैं, जिसके कारण एक साथ कई सारे लोगों तक गलत सूचना पहुँच जाती है ।

3. व्यवसायीकरण एवं टीआपी का दबाव -

टी आर पी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि एक न्यूज चैनल की या किसी कार्यक्रम या मनोरंजन चैनल की कितनी प्रसिद्धि है और उसे कितने लोग पसंद करते हैं, अतः वर्तमान में न्यूज चैनल टी आर पी बढ़ाने के लिए सनसनीखेज और अतिरंजित खबरें दिखाते हैं ।

बड़े उद्योगपति और कंपनियॉ मीडिया हाउसों को फंडिग देकर अपने पक्ष में खबरें प्रसारित करवाते हैं, उदाहरण के लिए कुछ चैनल या अखबार किसी विषेष उद्योग समूह के खिलाफ नकारात्मक खबरें प्रकाषित नहीं करते क्योंकि वे उन्हीं से विज्ञापन लेते हैं ।

मीडिया का व्यवसायीकरण वर्तमान में एक गंभीर मुद्दा बन गया है, समाचार का उदेष्य पहले जनता को निष्पक्ष और सत्य जानकारी देना था, लेकिन अब मीडिया संस्थान टी आर पी, विज्ञापनों और कॉरपोरेट हितों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसके कारण समाचारों की प्रस्तुति और प्राथमिकताएॅं प्रभावित हो रही है ।

International Conference – 2025: Developed India @ 2047
Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025
Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

4. पेड न्यूज (ब्रेकिंग न्यूजं) -

कुछ मीडिया संस्थान या पत्रकार पैसे लेकर किसी राजनीतिक दल, नेता या कॉरपोरेट कम्पनी के पक्ष में खबरें प्रकाषित करते हैं उदाहरण स्वरूप चुनाव के समय उम्मीदवारों के पक्ष मेंझूठी या एकतरफा खबरें प्रकाषित करना ।

वास्तविक मुद्दों की गहराई से पड़ताल करने के बजाए चैनल हर छोटी घटना को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेष करते हैं ताकि दर्षकों को बॉध कर रखा जा सके । मीडिया के कवरेज में भी काफी बदलाव आया है, कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया व्यक्ति केन्द्रित हो चुका है, ऐसा लगता है कि मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भाग रहा है, सामाजिक खबरें कम दिखाई देती है, वहीं अखबारों में विज्ञापन ज्यादा और खबरें कम दिखाई देती है ।

5. पत्रकारों पर हमले -

पत्रकारों पर होने वाले हमले लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गम्भीर खतरा है , पत्रकारों का मुख्य कार्य सत्ता, प्रषासन और समाज में हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार को उजागर करना होता है लेकिन कई बार उन्हें अपनी रिपोर्टिंग के करण शारीरिक हमले, धमकियॉ या कानूनी मामलों का सामना करना पड़ता है कई बार सरकारें या राजनीतिक दल पत्रकारों पर हमला करवाते हैं या उन्हें डराने की कोषिष करते हैं ताकि वे सच्चाई उजागर न कर सके ।

अपराध, घोटालों और भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को माफिया और संगठित अपराधी निषाना बनाते हैं, बड़े उद्योगपति अपनी नकारात्मक रिपोर्टिंग रोकने के लिए पत्रकारों को धमकाते हैं या कानूनी मुकदमों में फॅसा देते हैं । डिजिटल दौर में पत्रकारों को ऑनलाईन धमकियॉ मिलना आम हो गया है, खासकर जब वे किसी संवेदनषील मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते हैं ।

चुनौतियों के लिए कुछ आवष्यक कदम -

प्रष्न यह उठता है कि मीडिया के पक्षपातपूर्ण एवं व्यवसायिक हितों से प्रभावित होने से कैसे रोका जाए, जिसे दूर करने के लिए कई आवष्यक कदम उठाये जा सकते हैं , चूॅकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाचारपत्रांे या प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए श्ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950” मुकदमें के निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि

समाचारपत्रों पर पूर्व अवरोध लगाना प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात है, परन्तु इससे यह समझना कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई अंकुष नहीं है, गलत है, राज्य को प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, यदि वह देखता है कि प्रेस ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे हिंसा, घृणा, साम्प्रदायिक विघटनकारी आदि तत्वों के हाथ मजबूत होते है।

44वें संषोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 361 -ए के अंतर्गत समाचारपत्रों को सदन तथा विधान पालिकाओं की कार्यवाही को प्रकाषित करने की स्वतंत्रता सामान्य काल के अलावा संकटकाल में भी होगी। देष की अखंडता, शांति, नैतिकता न्यायालयों के सम्मान, विदेषी मैत्री संबंधों आदि विषयों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ।

1. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देना -

वर्तमान में मीडिया को सर्वप्रथम व्यवसायिक और राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर काम करने की आवष्यकता है, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मीडिया को सरकार और कॉरपोरेट हस्तक्षेप से बचना होगा, साथ ही सरकार को मीडिया की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र प्रेस को संरक्षण दिया जाना चाहिए । बड़े कॉरपोरेट हाउस और राजनेताओं के स्वामित्व वाली मीडिया कम्पनियों से संपादकीय टीम को स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए ।

2. मजबूत एवं निष्पक्ष मीडिया रेगुलेषन -

सरकार से स्वतंत्र एक ऐसी मीडिया आयोग अथवा संस्था बनायी जानी चाहिए जो मीडिया की निष्पक्षता की निगरानी करे और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग पर कार्रवाई करे । **PCI-** प्रेसकाउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य मीडिया निकायों को मजबूत बनाने की आवष्यकता है, **PCI** की शक्तियॉ दो तरह से प्रतिबंधित है, पहला जारी दिषा निर्देष को लागू करने का उनका अधिकार सीमित है, उल्लंघन के मामलों में वह समाचारपत्रांे, एजेन्सियों, संपादकों और पत्रकारों को दंडित नहीं कर सकता ।

दूसरा च्ब्प् प्रेस के कामकाज का बस उपरी निरीक्षण कर सकता है, वह समाचारपत्रांे, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया पर तो मानक लागू कर सकता है, मगर इलेक्ट्रोनिक मीडिया जैसे कि रेडियो, टी0वी0 और इंटरनेट की समीक्षा नहीं कर सकता, इन प्रतिबंधों को हटाकर च्ब्प् को और अधिक मजबूत बनाने की आवष्यकता है, साथ ही जनता को भी जागरूक बनाना होगा, आम जनता कोे यह समझना जरूरी है

कि खबरों की सत्यता कैसे जॉचे और किस स्रोत पर विष्वास करें । स्कूल और कॉलेज में मीडिया, साक्षरता, पाठ्यक्रम जोड़े जाने चाहिए, ताकि लोग प्रचार और वास्तविक समाचार में अंतर कर सकंे ।

3. फेक न्यूज (झूठी खबरों) की समस्या को दूर करना -

डिजिटल और सोषल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ दुनिया भर में फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बन चुकी है इंटरनेट और सोषल मीडिया की विषालता के कारण यह जानना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है कि किसी खबर की सत्यता क्या है और इस खबर का उद्भव कहॉ से हुआ है । भारत में फर्जी खबरों से निपटने कें लिए कोई विषेष कानून नहीं है, जिसके कारण इसके प्रसार को बढ़ावा मिलता है ।

यद्यपि नफरत से भरे कंटेट बनाने वाले और इसे साझा करने वाले लोगों को (भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत सजा दी जा सकती है, किन्तु इंटरनेट की विषालता के कारण ऐसे लोगों की पहचान करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है । बीते कुछ वर्षो में श्फेक न्यूज) फैलाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और कई सोषल मीडिया प्लेटफार्म ने भी अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया है किन्तु इसके बावजूद एक सार्वभौमिक नियम के अभाव के कारण श्फेक न्यूजश् की समस्या से पूर्णतः निपटा नहीं जा सकता है ।

हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीविजन न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे कंटेट के विरूद्ध आ रही षिकायतों और श्फेक न्यूजश् की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तंत्र के विषय में केन्द्र सरकार से सूचना मॉगी है, साथ ही यह निर्देष दिया गया है कि यदि ऐसा कोई तंत्र नहीं है तो जल्द से जल्द इसे विकसित किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चेताया कि यदि वह इस प्रकार के किसी भी तंत्र को विकसित करने में विफल रहती है तो न्यायालय को मजबूरन यह कार्य किसी बाहरी संस्था को देना होगा ।

4. पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकार सुनिष्चित करना -

पत्रकारो पर होने वाले हमलों और धमकियों को रोकने के लिए कड़े कानून लागू किये जाने चाहिए, पत्रकारों को बिना किसी राजनीतिक या कॉरपोरेट दबाव के निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की सुविधा मिले, इसके लिए उनके रोजगार और वेतन की समस्या सुनिष्चित करनी होगी जो भी पत्रकार भ्रष्टाचार और अन्य संवेदनषील मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं उन्हे विषेष सुरक्षा दी जानी चाहिए ।

International Conference – 2025: Developed India @ 2047
Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025
Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

गैर लाभकारी पत्रकारिता और गैर लाभकारी मीडिया संगठनों को सर्मथन देना चाहिए । सरकार द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन सभी मीडिया संस्थानों को समान रूप से दिए जाने चाहिए, न कि केवल सरकार सर्मथक मीडिया को । निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया संगठनों को अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए । साथ ही पत्रकारों को अन्तराष्टी्रय मंचों पर अपनी समस्याओं और चुनौतियों को साझा करने का अवसर मिलना चाहिए ।

स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार मीडिया संस्थान, पत्रकार और जनता को मिलकर काम करना होगा । जब मीडिया पर किसी का दबाव नहीं होगा और पत्रकारों की सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और निष्पक्षता की गारंटी मिलेगी तभी सही मायनों में लोकतंत्र मजबूत होगा । हमे निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहिए और पक्षपातपूर्ण मीडिया से सतर्क रहना चाहिए ।

निष्कर्ष -

एक स्वस्थ जनमत और लोकतंत्र का बहुत नजदीकी संबंध है लोकतंत्र का स्तर जनमत पर ही निर्भर करता है वर्तमान में लोकमत के निर्माण में मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, किन्तु आज मीडिया की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं किन्तु इसकी सफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । कई मीडिया संस्थान, सरकार, राजनीतिक दलों और प्रषासन पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही कई घोटालों भ्रष्टाचार एवं अन्य सामाजिक मुद्दों को मीडिया द्वारा उजागर किया गया है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, महिला सुरक्षा आदि पर सरकार को जबाव देना पड़ रहा है अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में मीडिया चौथे स्तम्भ के रूप में जनता तक सूचना पहॅुचाने, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने एवं सरकार को जवाबदेह बनाने में कुछ हद तक सफल रही है ।

किन्तु वर्तमान मीडिया पर राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव बढ़ा है जिससे निष्पक्षता प्रभावित हुई है । टी आर पी, सनसनी खेज खबरें, और श्फेक न्यूजश् ने इसकी विष्वासनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं अतः निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाए श्फेक न्यूजश् पर कड़ी कार्रवाई हो, जनता को जागरूक किया जाए, ताकि वे मीडिया की विष्वासनीयता की पहचान कर सकें एवं पत्रकारों की सुरक्षा सुनिष्चित की जाए ।

अंततः मीडिया को अपनी मूल भूमिका -श्सत्य और निष्पक्षताश् की ओर लौटना होगा तभी पूरी तर सफल कहा जा सकता है ।

संदर्भ -

1. एडी आर्षीवादम् तथा कृष्णकान्त मिश्र - “राजनीतिक विज्ञान” एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0, संषोधित एवं परिवर्धित बारहवॉ हिन्दी संस्करण
2. डॉ0 श्री प्रकाष मणि त्रिपाठी - “राजनीतिक अवधारणाए एवं प्रवृतियॉ” स्वानदा प्रकाषन, 2018
3. डॉ0 बीकेष्वर प्रसाद सिंह -राजनीतिक के सिद्धांतश् स्टूडेण्ड्स फ्रेण्डस द्वारा प्र
4. आर0पी0अरोरा -श्डेमोक्रेसी एण्ड प्रेसश् ओमेगा पब्लिकेषन, 2006
5. एम0 एम0 शर्मा -“जनीतिक विज्ञान” (समाज, राज्य और सरकार तथा भारतीय संविधान एवं प्रषासन , सरस्वती हाउस प्रा0लि0 2006
6. “रोल-ऑफ-मीडिया-इन-सोसाइटी” https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf
7. वाहत-मेकानिज्म डू यू हेव अगेन्स्ट फेक न्यूज https://www.drishtiias.com/
8. स्रोत - द हिन्दू
9. डिप्लोमा, इंटलेक्चुअल-प्रोपर्टी-मीडिया-इंटरटेनमेंट-लॉ -https://lawsikho.com/कोर्स